

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

60 / 2017  
23.05.2017

- 1-ताराचन्द पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 2-रामकरण पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 3-रामलाल पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 4-बनवारी पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 5-हनुमान पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 6-राजेन्द्र पुत्र नाथू जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 7-गोविन्द पुत्र प्रताप जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट्स

बनाम

- 1-ओंकार पुत्र रामा जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
- 2-चिरंजीलाल पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 3-रामेश्वर पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 4-सुरेश पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 5-स्थुवीर पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 6-मुकेश पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 7-मु०गंगा बेवा कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 8-हरजी पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 9-लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक
- 10-राजाराम पुत्र कोरीलाल जाति रेगर निवासी गंगापुरा तहसील निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 27.02.2017 अन्तर्गत धारा 183  
बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी ओंकार आदि बनाम ताराचन्द आदि

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलांट्स  
(2) श्री तेजमल जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 27.02.2017 को अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा मे से 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गंगापुरा पर अपीलान्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50



जिला कलेक्टर  
टोंक

गुणा राशि शास्त्रि के रूप में दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गहनता पूर्वक अवलोकन किया बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183 बी राज 0 टिनेन्सी एक्ट के तहत जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध पारित किया गया है, क्योंकि अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेण्ट्स दोनों ही रेगर् जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं, उक्त धारा में कार्यवाही तभी ही चलने योग्य होती है जब भूमि अनुसूचित जाति की हो तथा उस पर सवर्ण व्यक्ति का कब्जा काश्त हो, परन्तु तथाकथित प्रकरण में दोनों सदस्य अनुसूचित जाति से हैं। विवादित भूमि वर्षों पूर्व से ही आबादी भूमि है और मौके पर अपीलांट्स व अन्य व्यक्तियों के पुख्ता मकान व बाड़े आदि बने हुये हैं। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि पर बने हुए मकानों पर बिजली व नल के कनेक्शन ले रखे हैं, उक्त भूमि कृषि भूमि के उपयोग की भूमि भी नहीं है। भूमि पर आबादी बसी होने से रेस्पोंडेण्ट्स को सिविल न्यायालय के समक्ष बेदखली का वाद दायर करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त निर्णय पारित किया है। पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि इस भूमि में गांव की आबादी बसी हुई है, पूरे गांव के लोगो का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट्स ने उक्त भूमि को रेस्पोंडेण्ट्स से क्रय करने के उपरान्त ही मकानों का निर्माण कार्य किया है। रेस्पोंडेण्ट्स की नियत में बेईमानी व जमीनो की कीमते बढ़ जाने से अपीलांट्स से पुनः रकम ऐठने की नियत से यह कार्यवाही की गई है। अपीलांट्स के अलावा भी उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के मकान बने हुये हैं, परन्तु प्रकरण में उनके पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स ने जवाबी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोंडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित में सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये हैं। अपीलांट्स ने रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर पक्के मकानात, बाड़े व लकडिया डालकर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी दिनांक 14.07.2009 पृष्ठ संख्या 428-31 उद्धरित किये हैं।



जिला कलेक्टर  
टॉक

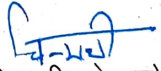
हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2068-71 वाके ग्राम गंगापुरा तहसील निवाई मे आराजी खसरा 01 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलाण्ट्स का तर्क है कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी मे कार्यवाही तभी ही चलने योग्य होती है जब भूमि अनुसूचित जाति की हो तथा उस पर सर्वण व्यक्ति का कब्जा काशत हो, परन्तु न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2013 (2) पृष्ठ संख्या 1272-74 से स्पष्ट है कि जब दोनो पक्षकार अनुसूचित जाति के है तो भी 183 बी के प्रावधान लागू होते है। अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो मे अंकित किया है कि उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट्स से कय करने के उपरान्त ही मकानो का निर्माण कार्य किया है, परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है।

अपीलाण्ट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा मे से 1 बिघा 10 बिस्वा वाके ग्राम गंगापुरा पर पांच पक्के कमरे, बाडे, लकडिया डालकर तथा पडत कब्जा किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्ध है कि अपीलाण्ट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काशत है जो राज0 काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 27.02.2017 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोंक  
टोंक